WESTERN RAILWAY

P.S.No.73/2012

Headquarter Office,
Churchgate, Mumbai-20

No. EP (PC)767/0

Date: 06.08.2012

To,
All DRMs / CWMs & Units Incharge,
C/- Genl. Secy., WREU-GTR / WRMS-BCT.
C/- GS-All India SC/ST Rly Employees. Assn,'W' Zone, Mumbai
C/- GS-All India OBC Rly Empl. Assn, Mumbai.

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – Clarification regarding proviso under Rule 10.

==========

A copy of Railway Board's letter No. PC-VI/2010/1/6/2 dated 18.07.2012 (RBE No.83/2012 PC-VI/296) is sent herewith for information, guidance and necessary action.

Encl: As above.

6/8/2012.

(S. Kademani)
For General Manager(E)

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(Railway Board)

S. No. PC-VI/296
No.PC-VI/2010/I/6/2

RBE No. 83/2012
New Delhi, dated 18.07.2012

The GMs/CAOs(R),
All Indian Railways & Production Units
(As per mailing list)

Sub: Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008 – Clarification regarding proviso under Rule 10.

Railway Board's Notification GSR 643(E) dated 04.9.2008 and letter No.PC-VI/2008/I/RSRP/1 dated 11.02.2009 and No.PC-VI/2010/I/RSRP/3 dated 23.04.2010.

References have been received from some of the Railways seeking clarification regarding computation of the period of one year for which pay was drawn at the maximum of the pre-revised scale towards admissibility of additional increment under proviso to Rule 10 of Railway Services (Revised Pay) Rules, 2008.

2. The matter has been examined and it is clarified that the increment in question will be admissible to all those employees who were stagnating at the maximum of their pay scale for more than one year as on 01.01.2006 including those who were in receipt of stagnation increment(s). It is also clarified that the one year period is to be reckoned w.e.f. the date of drawal of pay at the maximum of scale and not from the date of drawal of stagnation increment.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of the Ministry of Railways.

(HARI KRISHAN)
Director, Pay Commission-II
Railway Board.

भारत सरकार
रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

क्रम सं. पी सी- VI/296
सं. पी सी-VI/2010/I/6/2

आर बी ई सं. 83/2012
नई दिल्ली, दिनांक 18.07.2012.

महा प्रबन्धक / मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (रेलें)
सभी भारतीय रेलें एवं उत्पादन इकाइयाँ
(डाक- सूची के अनुसार)

विषय : रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008- नियम 10 के परन्तुक के बारे में स्पष्टीकरण.

सन्दर्भ : रेलवे बोर्ड की 04.09.2008 की अधिसूचना जी एस आर 643(अ), और 11.02.2009 का पत्र सं. पी सी-VI/2008/I/आर एस आर पी/1 एवं 23.04.2010 का पत्र सं. पी सी-VI/2010/I/आर एस आर पी/3.

कुछ रेलों से ऐसे संदर्भ प्राप्त हुए हैं जिनके द्वारा रेल सेवा (संशोधित वेतन) नियम, 2008 के नियम 10 के परन्तुक के अन्तर्गत् एक अतिरिक्त वेतन-वृद्धि की स्वीकार्यता के लिए पूर्व-संशोधित वेतनमान के अधिकतम पर एक वर्ष की अवधि की गणना के बारे में स्पष्टीकरण की अपेक्षा की गई है ।

2. मामले के परीक्षण के बाद स्पष्ट किया जाता है कि उपरोक्त 'वेतनवृद्धि' उन सभी कर्मचारियों को स्वीकार्य होगी जो 01.01.2006 को एक वर्ष से अधिक अवधि तक अपने वेतनमान के अधिकतम पर रुके हुए थे जिनमें वे कर्मचारी भी शामिल हैं जो पहले ही गत्यावरोध वेतनवृद्धि(वेतनवृद्धियाँ) आहरित कर रहे थे । यह भी स्पष्ट किया जाता है कि एक वर्ष की अवधि वेतनमान के अधिकतम पर वेतन आहरण की तारीख से प्रभावी मानी जाएगी; गत्यावरोध वेतनवृद्धि के आहरण की तारीख से नहीं ।

3. इसे रेल मंत्रालय के वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है ।

(हरि कृष्ण)
निदेशक, वेतन आयोग- II
रेलवे बोर्ड